

THE MINISTLR OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRAM AUR PUNARVAS MANTRI) (SHRI R K KHADILKAR)

(a) and (b) Rehabilitation of families who entered Tripura during the year 1970-71 forms part of the over-all programme of rehabilitation of new migrants who had entered the border States. The families are moved to transit camps at Mana and elsewhere and from there to rehabilitation sites in a phased programme correlated to the progress of the Rehabilitation Projects. Agriculturist families are resettled on land in the existing rehabilitation projects Maharashtra, Madhya Pradesh, Mysore etc. They are also resettled in Dandakaranya. Various State Governments have also been requested to provide additional land to cope with the increased requirements. The non agricultural families are resettled under various schemes, including the grant of business loans and employment in industrial schemes.

Out of 5818 persons who entered Tripura during 1970-71, 5305 persons were admitted to camps in Tripura. Out of the 5,305 persons admitted to camps in Tripura, 3,846 persons have already been shifted from Tripura in the process indicated above. 1,000 persons are being shifted shortly. The balance consists mainly of persons of Long Term Liability Categories who will be provided accommodation in the Permanent Liability Homes in Tripura.

Resettlement of Landless Agricultural Labour in Tripura

596 SHRI DASARATHA DEB Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION (SHRAM AUR PUNARVAS MANTRI) be pleased to state

(a) whether there is any scheme for the resettlement of landless agricultural labourers in Tripura

(b) if so, the details thereof and

(c) how far the Scheme has been implemented?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRAM AUR PUNARVAS MANTRI) (SHRI R K. KHADILKAR) (a) Yes

(b) The scheme was taken up for the first time during the Third Plan period and relates to resettlement of landless agricultural labourers other than Scheduled Castes, Tribes and Refugees

During the Fourth Plan period it is intended to resettle 1500 families @ 300 families per year at a cost of Rs 29 00 lakhs

(c) During the Third Plan period 840 families were rehabilitated

Supply of Foodgrains to Tripura

597 SHRI DASARATHA DEB Will the Minister of AGRICULTURE (KRISHI MANTRI) be pleased to state

(a) the total amount of foodgrains (rice and wheat separately) allotted to Tripura during 1970-71 and April 1971

(b) whether in view of the recent development in 'Bangla Desh and in view of heavy influx of displaced persons this allotment will be increased,

(c) the total amount of Rice and Atta already despatched to Tripura from Centre during this period and

(d) whether this despatched quantity is inadequate?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRAI) (SHRI ANNASAHIB SHINDE)

(a) While the allotments of rice from Central pool to Tripura are made for the whole of a calendar year those of wheat are made on a monthly basis. For the calendar year 1971, allotments amounting to 22.5 thousand tonnes have so far been made to Tripura. For the calendar year 1970, the quantity of rice actually supplied to Tripura from the Central pool was 15.5 thousand tonnes.

The total quantity of wheat allotted to Tripura during the financial year 1970-71 was 3,000 tonnes. The allotment of wheat made to them for April 1971 is 2 th tonnes.

(b) The additional requirements of Tripura Government for East Pakistan evacuees also be met.

(c) Against the allotments of 22.5 th. tonnes of rice made for the calendar year 1971. 13.3 th. tonnes has already been despatched. The quantity of wheat despatched to Tripura during the financial year 1970-71 was 2.2 th. tonnes. The quantity despatched during April 1971 was 205 tonnes. Further despatches are in progress.

(d) No, Sir.

राजस्थान में अकाल राहत कार्यों का पूरा किया जाना

597. श्री शिवनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान के उन दश जिलों में प्रत्येक में जिन्हें वहाँ अकाल पड़ने के कारण पिछड़ा हुआ समझा जाता है अपूर्व अकाल राहत कार्यों को पूरा करने के लिए दो करोड़ रुपये की लागत की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उनके चयन का क्या आधार है ,

(ग) क्या सरकार का विचार झुझुनू और सीकर जिलों में पानी तथा वर्षा की कमी, और उन क्षेत्रों के प्रतिवर्ष अकालग्रस्त हो जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों जिलों को उक्त योजना में शामिल करने का है ;

(घ) जिन जिलों को योजना द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए चुना गया है क्या सीकर और झुझुनू जिलों की हालत उनसे अधिक खराब है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)

(क) निरन्तर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये ग्राम निर्माण कार्यक्रम के आधीन, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, बनारोपण और संचार सुविधायें जैसे क्षेत्रों में श्रम वाली और उत्पादनोन्मुखी योजनायें अपनाई जाती हैं। राजस्थान राज्य में इस कार्य-

क्रम के कार्यान्वयन के लिये जैसलमेर, बारमेर, पाली, जालौर, बीकानेर, चुरू, जोदपुर, बसवाड़ा नागीर, और डूंगरपुर नामक 10 जिले चुने गये हैं। चुने गये प्रत्येक जिले के लिए, चौथी योजना काल में लगभग 2 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया जायेगा। यद्यपि, कार्यक्रम का मंतव्य अधूरे अकाल राहत कार्यों को पूरा करना नहीं है, तथापि यदि अन्य शर्तें पूरी होती हों तो ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) ग्राम निर्माण कार्यक्रम जिलों का चुनाव जो सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के केन्द्र बिन्दू है, वहाँ के सूखे की स्थिति पर किया जाता है। यह स्थिति वहाँ कितनी बार और कैसी वर्षा होती है, कितनी अवधि और किम सीमा तक सूखा पड़ता है, जिले में कुल फसल आधीन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में मिंचाई होती है और अन्य सम्बन्धित तथ्यों जैसी वास्तविक कमीटियों से जानी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिये कार्यवाही

599. श्री शिवनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) 1970 वर्ष की तुलना में 1971 वर्ष के दौरान गेहूँ, चना, चावल तथा बाजरा जैसे कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट की प्रतिशतता क्या थी और इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट की रोकने में असफल रहा और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई,